Newspaper Clips

November 30, 2016

Nav Bharat Times ND 30.11.2016 P-5

IIT में एरोमॉडलिंग सेलिब्रेशन

Katyayani.Upreti
@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : आईआईटी दिल्ली में पहली बार स्कूलों के स्टूडेंट्स को एरोमॉडलिंग के फंडे सिखाए जाएंगे। साथ ही, स्कूल लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए एरोमॉडलिंग कॉम्पिटिशन भी होगा। आईआईटी के साथ मिलकर भारत की एक एरोमॉडलिंग कंपनी यह आइडिया लेकर आई है ताकि स्कूल से ही स्टूडेंट्स को एरोनॉटिकल इंजिनियरिंग, एविएशन जैसे फील्ड में खुद को आगे बढ़ाने का मौका मिले। इवेंट 3 दिसंबर को आईआईटी कैंपस में नालंदा ग्राउंड पर होगा। स्टूडेंट्स 2 दिसंबर तक रजिस्टर कर सकते हैं।

एरोमॉडलिंग को हॉबी और स्पोर्ट्स के तौर पर प्रमोट करने वाली एरोमॉडलिंग कंपनी इंडियाज हॉबी शैक इस इवेंट को आईआईटी लेकर आ रही है। कंपनी के ओनर दीपक शर्मा का कहना है कि हॉबी के साथ-साथ एरोमॉडलिंग ऐसी क्रिएटिव हॉबी है, जो डिजाइनिंग और बिल्डिंग दोनों को कवर करती है। हेलिकॉप्टर, रॉकेट, एयरप्लेन के मॉडल बनाने और उड़ाने में एरोबैटिक्स के फंडे का इस्तेमाल होता है। आईआईटी में इस इवेंट के साथ हमारा यही मकसद है कि जो स्टूडेंट्स एरोबैटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, वे एरोमॉडलिंग से जुड़े एरोनॉटिकल इंजिनियरिंग, एविएशन जैसे टेक्निकल फील्ड में बढ़ने की सोचें और इस इवेंट के जरिए वे आगे के लिए तैयार हो सकें।

3 दिसंबर को आईआईटी के नालंदा ग्राउंड्स में यह इवेंट सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 150 से ज्यादा स्कूल इस ग्रैंड इवेंट 'इंटर स्कूल एरोमॉडलिंग कॉम्पिटिशन' का हिस्सा बनेंगे। कॉम्पिटिशन तीन लेवल में 8 से 17 साल के स्टूडेंट्स के बीच होगा। इवेंट में स्कूल ही नहीं बल्कि अलग से भी स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। एरोमॉडलिंग इंडस्ट्री में 25 साल के एक्सपीरियंस और एरोमॉडलिंग एजुकेशन में पांच साल के सेलिब्रेशन के बाद इस कंपनी का आईआईटी में स्कूली स्टूडेंट्स के लिए यह पहला इवेंट है। साथ ही एरो क्लब ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट इस इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस 200 से 400 रुपये है।

Navoday Times ND 30.11.2016 P-7

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे यमुना पर पुल बनाने की एनजीटी से मिली मंजूरी

❑ आईआईटी दिल्ली, रुड़की के इंजीनियर नियुक्त होंगे

नई दिल्ली, 29 नवम्बर (ब्यूरो): यमुना पर पुल बनाने के मसले पर लंबे अर्से से अटका हुआ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट अब जल्द ही शुरू हो सकेगा। एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए यमुना पर पुल बनाने को मंजूरी दे दी है। एनजीटी की प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय दिया गया है। रिपोर्ट में कमेटी ने पुल की जरूरत और पर्यावरण को इससे किसी तरह का नुकसान न पहुंचने के साथ ही फायदेमंद साबित होने वाला बताया है। हालांकि एनजीटी ने मंजूरी देते समय यह शर्त अवश्य जोड़ दी है कि एनएएचएआई इस पुल के निर्माण के दौरान आईआईटी दिल्ली अथवा रुड़की के इंजीनियरों को नियुक्त रखेंगे। ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी निर्माण के दौरान न हो सके और निर्माण की वजह से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हाल ही में एनएचएआई के आला अधिकारी ने भी कहा था कि जल्द ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने पुल निर्माण के लिए एनजीटी से मंजूरी न मिलने को सबसे बड़ी समस्या भी कहा था।

एनजीटी में एनएचएआई ने बताया कि दिल्ली से मेरठ जाने के लिए एनएच-58 पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों का खासा समय और ईंधन बर्बाद होता है। ऐसे में एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट पूरा होने से लोगों के समय और ईंधन की बचत होगी। साथ ही तीन घंटे का सफर महज 45 मिनट में पूरा हो सकेगा।

एनजीटी को प्रिंसिपल कमेटी ने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के बनने से पर्यावरण को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। क्योंकि जाम के कारण वाहनों से निकलने वाला धुंआ और ईंधन की बर्बादी रुकेगी। यमुना पर पुल बनाने के दौरान भी किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा।

गौरतलब है कि एनजीटी ने 2015 में आदेश दिया था कि किसी भी नए पुल, रेलवे, मेट्रो ब्रिज का प्रोजेक्ट आरंभ करने से पहले एनजीटी से मंजूरी लेनी होगी और आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा। पीपीपी मोड पर तैयार होने वाला यह एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट निजामुद्दीन से शुरू होकर मेरठ तक [illegible] से पहुंचेगा।

इसके लिए कई चरण का टैंडर भी हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2015 को इसका शिलान्यास किया था। करीब 96 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है और इसके चौड़ीकरण का काम चार हिस्सों में बांटा गया है।

Nai Duniya ND 30.11.2016 P-14

नया शोध आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित की चिकित्सकीय पट्टी

रेशम की पट्टी पर लगा शहद ठीक करेगा मुंह के कैंसर का घाव

कोलकाता। ब्यूरो

शहद से मुंह के कैंसर के घाव का कारगर इलाज संभव है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने एक चिकित्सकीय पट्टी विकसित की है। रेशम की बनी इस पट्टी पर शहद का लेप लगा हुआ है। इसे ईजाद करने वाली टीम में केमिकल इंजीनियर, बायो-टेक्नोलॉजिस्ट एवं डॉक्टर शामिल हैं।

आईआईटी खड़गपुर के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लैब में किए गए प्रयोग में सामने आया है कि यह औषधीय पट्टी न सिर्फ कैंसर के घाव को तेजी से भरती है बल्कि फिर से कैंसर होना भी रोकती है। पट्टी की मेंब्रेन शीट को रेशम से इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि यह लचीला होता है और मानव शरीर के साथ जैविक रूप से अनुकूल है। टीम में शामिल मोनिका राजपूत ने बताया कि शहद को उसकी घाव सुखाने की क्षमता, कैंसर रोधी एवं एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। इस पट्टी में शहद के इस्तेमाल का विचार टीम में शामिल ज्योतिर्मय चटर्जी ने दिया है। सह-अनुसंधानकर्ता नंदिनी भंडारू ने बताया कि मुंह का कैंसर होने पर बहुत से मरीजों की सर्जरी कर प्रभावित हिस्से को काटकर निकाल दिया जाता है, जिससे वहां एक घाव हो जाता है, जिसमें कैंसर की कोशिकाएं रह जाती हैं। इससे फिर से कैंसर होने की आशंका बनी रहती है। हमारी तकनीकी इस तरह के घावों को भरने में मदद करती है। वर्तमान समय में बाजार में मुंह के कैंसर के घाव के लिए कोई वैसी चिकित्सकीय पट्टी उपलब्ध नहीं है, जो घाव को तेजी से सुखा सके और इसे दोबारा होने से रोक सके। पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है और इस अनुसंधान रिपोर्ट को अमेरिकन केमेस्ट्री सोसायटी के बायोमैटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस तकनीक का वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल से पहले इसका जानवरों एवं उसके बाद मानव शरीर पर प्रयोग किया जाएगा।

Hindustan ND 30.11.2016 P-9

विदेशी डॉक्टर भी देश में इलाज कर सकेंगे

सुविधा

नई दिल्ली | मदन जैड़ा

आईआईटी में विदेशी प्रोफेसरों की नियुक्ति करने के बाद केंद्र सरकार अब विदेशी डॉक्टरों को भी देश में डॉक्टरी की इजाजत दे रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश पर एमसीआई ने विदेशी डॉक्टरों को बिना किसी टेस्ट के अस्थाई रजिस्ट्रेशन देने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस संदर्भ में जल्दी अधिसूचना जारी करेगा।

एमसीआई के सूत्रों के अनुसार कुछ समय पूर्व एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई जिसमें विदेशी डॉक्टरों को भारत में काम करने की इजाजत है।

अभी तक शोध, पढ़ाई आदि कार्य के लिए ही विदेशी डॉक्टर आते थे जिसके लिए उन्हें अस्थाई पंजीकरण नंबर एमसीआई देती थी। लेकिन अब डॉक्टरी करने के लिए भी यदि वे भारत आना चाहेंगे तो एमसीआई उन्हें तुरंत अस्थाई नंबर देगी। वे किसी अस्पताल में बतौर डॉक्टर कार्य कर सकेंगे।

टेस्ट नहीं देना होगा

भारत में एमसीआई का पंजीकरण पाने को विदेशों में पढ़े डॉक्टरों को स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है। सिर्फ पांच अंग्रेजी भाषी देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया को प्रावधान से छूट है। लेकिन नए प्रावधान के अनुसार विदेशों में पहले से डॉक्टरी कर रहे चिकित्सक भारत में अस्थाई पंजीकरण प्राप्त कर सेवा दे सकेंगे।

छह लाख डॉक्टरों की कमी

देश में करीब छह लाख डॉक्टरों की कमी होने का अनुमान है। भविष्य में चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए हर साल एक लाख एमबीबीएस तैयार करने की जरूरत है लेकिन सीटें 60 हजार तक ही पहुंच पाई हैं।

स्वदेश वापसी की राह खुलेगी

इस फैसले से भारतीय मूल के डॉक्टरों की भी स्वदेश वापसी की राह खुलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्व में इसके लिए एक पोर्टल बनाया था जिसमें भारतीय मूल के डॉक्टरों का पंजीकरण कराया जा रहा है।

टोनी ब्लेयर की तर्ज पर पहल

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हुए टोनी ब्लेयर ने बड़े पैमाने पर विदेशों से चिकित्सकों, खासकर मनोरोग और दांतों के डॉक्टरों को बुलाकर दूरदराज के इलाकों में तैनात किया था। इस प्रकार वहां डॉक्टरों की कमी दूर की गई थी। बड़ी संख्या में भारत से डॉक्टर ब्रिटेन गए और अभी तक नहीं लौटे। खबर है कि इसी तर्ज पर भारत भी अन्य देशों से डॉक्टरों को भारत बुला सकता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से डॉक्टर रोजगार के लिए भारत आ सकते हैं। इन देशों में डॉक्टरी का स्तर भी अच्छा है।

Times Of India ND 30.11.2016 P-1

Big bang by academic institutes at IIT-B

Arrival For Placements Up 3 Times

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: For a long time, blue chip companies, investment firms and startups ruled the first edition or Phase I of placements at the Indian Institutes of Technology. However, Phase I has seen academic institutes jump up the charts this recruitment season.

IIT-Bombay has seen a three-fold increase in the number of academic institutes visiting its campus this December. While seven institutes had signed up to recruit teaching talent last year, 20 have already registered this time round, said placement head Tom Mathew. Most are Indian universities, many of them private and deemed institutions that draw teachers from top-rung campuses.

"Close to 10% of our total recruiters are academic institutes this year, which means a lot of options for our doctoral candidates," said a member of the placement committee.

At IIT-Kanpur, 15 academic institutes have registered to choose faculty members from among the masters and PhD students.

N P Padhy, professor-in-charge of training and placement at IIT-Roorkee, said they were seeing a similar trend this year. "Generally, academic institutes visit the campus after December. Six institutes or universities have already been registered this year," he added.

Manu Santhanam of IIT-Madras said that a clear picture on the exact number would emerge only next semester, as academic institutes hire until May-June. "There is no fixed time limit for them, as they are mostly interested in research scholars," he said.

Prakash Gopalan, vice-chancellor of Thapar University, said they had been recruiting PhDs from the IITs because the students there are inclined towards research.

Sandip Jha, chairman of Sandip University, said there were plans afloat to model their engineering school on the lines of the IITs. "For that we need the best possible faculty in the country. Hence, we have empanelled ourselves with all the IITs and the NITs," he added.

However, the IITs have not yet seen too many international campuses travelling to pick freshers. In 2009, among the many universities shopping for faculty members was Alfaisal University from Saudi Arabia, which landed uat several IITs and offered an annual compensation of approximately Rs 17 lakh, apart from housing and other facilities. Texas A&M University, seeking to recruit for its Qatar campus, came to IIT-Madras.

The remuneration offered by Indian institutes is less than half that given by their international counterparts. A faculty member at IIT-Bombay pointed out that "a very small number of MTechs" take up teaching jobs. "At the end of the placement season, it will be interesting to be see how many of these universities actually get serious students," he added.

PLACEMENT SEASON DYNAMICS AT IIT-B

- Placement season at IIT-Bombay will begin on Dec 1 and see recruiters line up till Dec 15
- Core placements at IIT-B are expected to increase significantly this season, with several public sector units (PSUs) and universities and colleges approaching the institute
- In addition to Isro, Coal India and HPCL which visited IIT-B last year, the new PSUs include ONGC, BPCL and Bharat Electronics Ltd, among others
- They are expected to hire students across Bachelors, Masters and Doctoral programs. These PSUs are offering competitive packages. Students of the institute have also shown more interest in taking up core jobs than last year
- So far, 125 PPOs have visited and the core engineering sector has the highest registrations
- Demand for data analytics role is unchanged
- Deferral placements are permitted only for startup and social cases
- Further, colleges and universities are looking for high-quality hires to fill educational roles

Hindustan Times ND 30.11.2016 P-19

In growth push, e-wallet firms eye 200 hires from IITs, IIMs

Rozelle Laha
rozelle.laha@hindustantimes.com

The demonetisation drive has brought good news for fresh graduates of top colleges as mobile wallet firms plan to expand business operations due to a surge in wallet transactions.

Paytm, the largest mobile payments and commerce platform, plans to recruit 100 graduates this year. MobiKwik will recruit nearly 200 people and strengthen its sales, marketing and business development departments.

Since the government demonetised ₹500 and ₹1,000 notes on November 8, Paytm has added five million new users and registered over seven million transactions worth ₹120 crore in a day. Mobikwik with a user base of 40 million has seen a growth of 40% in daily app downloads.

MOBIKWIK WILL RECRUIT NEARLY 200 PEOPLE IN ORDER TO CREATE A BRAND. PAYTM TO HIRE 100 GRADS.

"We'll continue to hire freshers and experienced professionals across diverse roles to keep up with our growth," said Paytm's senior vice-president Amit Sinha.

Apart from IITs and IIMs, Paytm has in the past hired graduates from BITS Pilani, National Institutes of Technology, Indian Institutes of Information Technology, FMS Delhi, XLRI Jamshedpur, MDI Gurgaon, SP Jain Institute of Management and Research, Mumbai, and Indian School of Business, Hyderabad.

"This year will be no different," Sinha added.

MobiKwik plans to hire 100 graduates from IITs and IIMs at an average annual salary of ₹15 lakh. "Over the next six months, we plan to invest 10 million dollars on team expansion and increase the team size from 210 to 400," said Bipin Preet Singh, founder and CEO, MobiKwik.

Freecharge, owned by e-commerce giant Snapdeal, refused to divulge any details. Company CEO Govind Rajan said, "Given the sharp increase in usage in recent weeks, we are expanding the customer acquisition team."

The final placements across all B-schools and engineering colleges will be held from December onwards.

IIT-Delhi, Tokyo university experts count dolphins in Ganga

http://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/IIT-Delhi-Tokyo-university-experts-count-dolphins-in-Ganga/articleshow/55695457.cms

KANPUR: Encouraged by frequent sightings of Gangetic dolphins in the Ganga at Bhitora Ghat in Fatehpur district, experts from IIT-Delhi, University of Tokyo and the Society for Conservation of Nature have launched a survey to find out the exact number of the endangered animal.

The experts are taking help of sonar monitoring systems and camera-fitted balloons in a 35-km stretch of the Ganga at Bhitora Ghat as part of efforts to conserve the endangered dolphin population in the river. The team conducting the survey will also assess threats to the dolphins in the river and help plan improvements in its habitat.

"We have deployed an experimental sonar monitoring system and raised camera-fitted balloons above the river Ganga to track dolphins by high-frequency clicks they use to navigate and hunt. By eavesdropping on their underwater lives, we can gather data about their behaviour and geographical range-data that conservationists can use to keep the species from vanishing entirely," said Harumi Sugimatsu, an acoustical engineer associated with the University of Tokyo's Institute of Industrial Science, who is part of the team.

Sugimatsu said, "Fifteen years ago, there were three species of freshwater dolphins in the world, living in the Ganga, Indus, Amazon, and Yangtze rivers. Now there are two. Chinas Yangtze dolphin has been considered extinct since 2006, when a research expedition surveyed about 3,500 km of the Yangtze without finding a single animal."

More findings, Sugimatsu said, may save the Ganges dolphins from that fate. "We are keen to understand their migration patterns," she said.

Dolphins clicks can reveal surprising details about their activities, such as the locations where they hunt, play, and nurse young calves. For which, Sugimatsu spends 10 hours daily at monitoring stations along key stretches of the river to keep tab on the roaming animals.

Sugimatsu said that the week-long expedition has been planned by Rajendra Bahl, a professor at the Centre for Applied Research in Electronics at the Indian Institute of Technology, Delhi.

Bahl's lab primarily does sonar work for the Indian navy. "I and Bahl began studying marine mammals together in the early 2000s, when we used to track migrating humpback whales around the islands of Japan," Sigimatsu informed TOI.

"It is encouraging that the Gangetic dolphins have been sighted at various places at Bhitaura ghat in the Ganga. Now, with the help of sonar monitoring system and camera-fitted balloons raised above the river, we will study the pattern of their migration and devise safety measures required at those places for them," Bahl said.

How the survey is being done

The hydrophone system dangles in the water suspended from a boat's prow. The line of individual hydrophones used to study the lonely dolphin has been replaced by a single piece of equipment holding six hydrophones. These sensors are arranged to pick up sounds coming from every direction, so they'll capture more sonar beams as passing dolphins scan back and forth. Each pair of hydrophones is like a pair of ears, Bahl said.

To locate the source of sounds, the system uses triangulation: A dolphin click travelling at the speed of sound through the water (roughly 1,500 meters per second) reaches one endpoint hydrophone a fraction of a millisecond before the other. The hydrophone in the middle acts as a 'third ear' to provide another data point, and thus more precision. The system then calculates how far that sound travelled to reach each hydrophone to determine the dolphins direction and distance. For every 40-microsecond click, the system runs the calculation for both sets of ears.

Bahl explained that the system can pinpoint a dolphin's location to within a few meters, making it precise enough to track individual creatures.

Financial Express ND 30.11.2016 P-8

Age equals quality for varsities

The differential impact of longevity on companies and varsities has important implications for education regulation

JANAT SHAH
& MANISH SABHARWAL

POET Alfred Tennyson said in *Morte d'Arthur*, "The old order changed, yielding place to the new and God fulfils himself in many ways lest one good custom should corrupt the world". Tennyson's wisdom is obvious in the brutal effect of age on companies; 90% of the first Fortune 500 list of 1955 and 75% of companies of the BSE Sensex 30 companies of 1991 are no longer on those lists. But universities seem different from companies. The youngest institution in the Top 10 global universities in 125 years old and only 4 institutions in the Top 100 are less than 40 years old. We would like to make the case that this differential impact of age on companies and universities has important implications for education policy.

Relentless creative destruction is good for the economy; the 1991 economic reforms are significant for India because they made political connections and regulatory arbitrage less important than courage, sweat, and wits and, thereby, increased churn. Age is tough on companies for many reasons. First is the Innovators' Dilemma popularised by Clayton Christenson; companies that have huge cash-flows from products or markets are often unwilling or unable to change their successful operating models in ways that lead to short-term disruptions of those cash-flow. Second, age leads to arteries hardening; cholesterol builds up and bureaucracies develop the status quo bias of "anybody can say no but nobody can say yes". The third and probably most fatal flaw is a shift in consumer preferences; consumers don't want their products because competition is offering something that is better, faster, cheaper, or just different.

Age is more complicated for universities. Global experience suggests that building a world-class university is the work of decades. Of course, it is hard to deny the costs of age—the decline of Allahabad University, Santiniketan and Calcutta University are obvious examples—or the few examples where new universities have catapulted to the top (ISB and Ashoka University piggybacked on the reputations of founders, faculty or old foreign institutions). On balance, age is probably good for universities for three reasons. First is the chicken-and-egg problem of establishing reputation and attracting good faculty. Software trumps hardware but a reputation takes time to build. Second is the alumni pool; a larger, diverse, and senior alumni pool improves the odds for universities to gain recognition, resources, and goodwill ambassadors. Third, and probably the most important, is that it takes time for processes to start flowing in their full glory. Muscle memory for flawless teamwork, curriculum, research, administration, and much else needs recognising the plane crash approach to quality (the only way to improve air traffic safety is to have plane crashes because if we knew something that would make things better, it would already be built in).

Since 80% of India's higher education and skill capacity of 2050 is yet to be built, the longevity insight has important implications for education policy. First, geography matters; the accelerating divergence in the last few decades between IITs in Mumbai & Delhi and Kanpur & Kharagpur reflects the economic complexity just outside their gates. So, it is better to bring students to education rather than take education to students. Second, education regulators must stop confusing university buildings with building universities and focus on outcomes rather than inputs; they must remember Harvard professor Lant Pritchett's warning to not confuse the accounting of accountability (did you follow process or checklist) with the account of accountability (did you do the right things). Third, government funding must learn about time horizons from small countries like Hong Kong, Singapore and Korea that have parachuted young universities in the Top 100. A 20-year-plan is not 10 two-year-plans. Third, regulators must stop thinking about failure as a problem; the divergent destiny of engineering education (30% empty capacity out of 15 lakh seats and 30% of colleges expected to shut down) and medical education (only 37,500 doctors with massive capitation fees) shows how India is better off with more open entry and exit that encourages a number of genetically diverse statistically independent tries. Fourth, institutions and their board should take a human capital view of faculty, e.g., one model could be that for the first eight years of career, a faculty member must focus on research and teaching output (helped by mentoring and collaboration), next eight years on research and teaching productivity (through doctoral students and application expertise), and finally, eight years of exploitation of application expertise (via books, mentoring, and external engagement). Finally, a relentless focus on governance—the allocation of decision rights—is crucial to building enduring institutions. The relative role of government, founders, funders, faculty, alumni and regulators needs to be continuously renegotiated. In the current Indian context needs a radical reboot because the most visible impact of good governance is institutional culture and values which are often hard to set with the regulatory drive towards standardisation. It is also clear that governance will be most effective is we unpack the role of the government as a regulator, service provider and policy maker. Regulators making policy not only stifles risk taking and innovation but creates a culture of differential standards.

Without hindering competition, we need to recognise that universities that are world-class are almost always varsities that are old. So, we need to figure out how to blunt bad ageing and amplify good ageing

The acceleration of creative destruction in corporate India since 1991 (companies with 80% of the market cap then are now less than 20%) has been wonderful for India's growth, productivity, social mobility, and economic complexity. Without hindering competition, we need to recognise that universities that are world-class are almost always universities that are old. So, we need to figure out how to blunt bad ageing and amplify good ageing. Policy-makers need to slow down and take the long view because the best universities echo the wisdom of poet Robert Browning: "Grow old with me for the best is yet to be".

Shah is director, IIM Udaipur, and Sabharwal is chairman, TeamLease Services. Views are personal